

# अनुगामिनी

बिहार में महागठबंधन नहीं महाठगबंधन की सरकार : रामसूत राय | 3 चुनाव केंद्रित सोच से शहरों का भला नहीं किया जा सकता : पीएम मोदी | 8

## एआरएस के लिए आवेदनों का अस्वीकृत किया जाना रूटीन प्रक्रिया का हिस्सा : दीपा रानी थापा

कहा— आवेदन पत्रों को 21 अक्टूबर तक फिर से किया जा सकता है जमा

अनुगामिनी का.सं.

गंगटोक, 20 सितम्बर। सिक्किम के सोशल मीडिया में पछतों दिनों छाये रहे सिक्किम लोक सेवा आयोग (एसपीएससी) द्वारा एसिस्टेंट रेवन्यू सर्वेयर (एआरएस) और लोअर डिवीजन क्लर्क (एलडीसी) के कुल 150 पत्रों पर नियुक्त प्रक्रिया में 8000 से अधिक आवेदन पत्रों को अस्वीकृत कर दिये जाने के मामतों में आज एसपीएससी सचिव ने इसे एक रूटीन प्रक्रिया बताया। उनके अनुसार आवेदन पत्रों में कमी या अपूर्णता के कारण ही उन्हें अस्वीकृत किया गया है और उसे पूरा कर किए गये थे आवेदन पत्र अस्वीकृत किये गये हैं। इन आवेदन पत्रों को 21 अक्टूबर तक फिर से जमा किया जा सकता है।

उन्होंने यही कि एसपीएससी एक रूटीन प्रक्रिया है। साथ ही उन्होंने यही बताया कि अस्वीकृत किये गये आवेदनों को नुस्खा स्वीकार किया जाता है। अस्वीकृत सूची में शामिल आवेदनों के फिर से 21 अक्टूबर तक जमा किया जा सकता है।

सचिव श्रीमती दीपा रानी थापा ने बताया कि इन से पत्रों के लिए ही कुल 25000 से अधिक आवेदन प्राप्त हुए हैं। इसलिए अस्वीकृत आवेदन पत्रों की संख्या इनी अधिक हुई है, जो लोगों को दिख रही है।

वहीं अन्य पत्रों के लिए इतने अधिक आवेदन नहीं मिले हैं। उनके अनुसार सामान्य नुस्खों, जैसे गलत नाम, पता, शैक्षणिक योग्यता, पहचान प्रमाणपत्र एवं ऐसे ही अन्य क्षेत्रों में मानदंडों को पूरा न किये जाएं पर आवेदन स्वतः रह हो जाते हैं। उन्होंने कहा कि वे सरकार ही अस्वीकृत किये गये हैं। इन अस्वीकृत आवेदनों की सूची प्रकाशित करना

वर्षीय राज्य के दूर-दराज के

एसपीएससी की अधिकारी ने बताया कि एसपीएससी के आवेदनों की फिर रही है और उनके आवेदनों को यूं ही अस्वीकृत नहीं किया जाता है। उनके अनुसार आवेदन पत्रों की जांच में एक ऑनलाइन प्रीलिमनरी प्रक्रिया है, जहां शैक्षणिक योग्यता, पहचान प्रमाणपत्र एवं ऐसे ही अन्य क्षेत्रों में मानदंडों को पूरा न किये जाएं पर आवेदन स्वतः रह हो जाते हैं।

जांच के बाद एसपीएससी की अधिकारी ने बताया कि एसपीएससी के आवेदनों की अस्वीकृत किया जाता है। उन्होंने कहा कि वे सरकार ही अस्वीकृत किये गये हैं। इन अस्वीकृत आवेदनों की सूची प्रकाशित करना

## पासंग शेरपा ने एसकेएम अध्यक्ष को भेजी कानूनी नोटिस

अनुगामिनी का.सं.

गंगटोक, 20 सितम्बर। राजनीतिक और सामाजिक कार्यकर्ता पासंग शेरपा ने सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा (एसकेएम) के अध्यक्ष तथा मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमाङ (गोले) को कानूनी नोटिस भेजा है। इसमें पार्टी के आधिकारिक मुख्यपत्र एसकेएम दर्पण में उनके एक लेख में कथित रूप से अपमानजनक, नस्तवारी और अपमानजनक टिप्पणी करने का आरोप लगाते हुए इसकी निंदा की गई है।

एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए पासंग शेरपा ने कहा कि पार्टी ने मेरी छवि और प्रतिक्रिया को बदलाया और खाब किया है इसमें झूठे, मनगढ़त और तुच्छ आरोप लगाए गए हैं, जो पूरी

तरह से निराधार और गलत हैं।

उन्होंने कहा कि आरोप झूठे हैं क्योंकि उमारी पुरुषी जमीन गैरीगांव (गद्दी खोला) जौबरी ब्लॉक, दामथांग ग्राम पंचायत, नामची जिला, सिक्किम, भारत के तहत पंजीयांवार्ड में स्थित है। उन्होंने कहा कि वे सरकार ही तथा इसे वे स्वयं सत्यापित करा सकते हैं।

उन्होंने आगे कहा कि मेरी पत्नी के खिलाफ उपरान्त अपमानजनक, अपमानजनक, जातिवादी और जातिवादी बयान दिया गया था कि वह गैर सिक्किमी हैं और सराव उठाए गए थे कि वह गैर सिक्किमी होने के नामे जमीन कैसे खरीद सकती है? यह आपकी जानकारी के लिए है कि वह ओल्ड सेटलर्स परिवार से हैं और मेरी कानूनी



क्षति पहुंचाई जा सके। शेरपा ने

एसकेएम दर्पण के पोस्ट को वापस लेने की मांग की है और सात 7 दिनों के भीतर बिना शर्त माफी मांगने की मांग की है। उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं करने पर, एसकेएम अध्यक्ष और उनकी राजनीतिक दल (सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा) के खिलाफ उचित नागरिक और आपराधिक कार्रवाई शुरू करने के लिए विवाह हो जाऊंगा।

शेरपा ने आगे उल्लेख किया कि यह एक दुर्भावनापूर्ण इरादे से किया गया है कृत्य है ताकि मेरे और मेरे परिवार की प्रतिष्ठा, नाम, प्रसिद्धि और सार्वजनिक प्रतिष्ठा को

## जीवन रक्षक पेशा है कृषि व पशुपालन : मंत्री शर्मा

अनुगामिनी का.सं.

गंगटोक, 20 सितम्बर। कृषि क्षेत्र में नयी तकनीकों पर जागरूकता, प्रशिक्षण तथा किसान-वैज्ञानिक परिचर्चा हेतु बायोटेक किसान हब सिक्किम विश्वविद्यालय, एमएसपी, सीईपीएचटी एवं सीएयू राजीवपुल द्वारा आज राजीवपुल कृषि विश्वविद्यालय में दो दिवसीय कार्यक्रम की शुरूआत हुई।

इस अवसर पर राज्य के कृषि, पशुपालन एवं पशु चिकित्सा मंत्री लोक नाथ शर्मा मुख्य अतिथि के तौर पर उपस्थित थे। वहीं उनके अलावा उद्घाटन कार्यक्रम में सिक्किम विश्वविद्यालय के उप-कृषिपति प्रो. अविनाश खेर, सीईपीएचटी डीन प्रो. पीपी डबराल के अलावा केंद्र सरकारी संगठनों, शैक्षणिक संस्थानों के प्रतिनिधियों, वैज्ञानिकों, किसानों एवं विद्यार्थियों ने भी शिरकत की।

इस अवसर पर मंत्री शर्मा ने मानव समाज की पूर्ण अनिवार्यता तथा जीवन रक्षक पेशे के तौर पर कृषि एवं पशुपालन पर जोर दिया। उन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि और बगवानी को बढ़ावा देने में सिक्किम विश्वविद्यालय और सीएयू की भूमिका के प्रति आभार व्यक्त करते हुए राज्य के मुख्यमंत्री के नेतृत्व में सरकार द्वारा कृषि क्षेत्र में उल्लेखनीय परिवर्तन लाने का कहा कि खेती की मुश्किलों को आसान बनाने और उत्पादकता वृद्धि

सुनिश्चित कर किसानों को लाभ पहुंचाने हेतु उन्हें तकनीकी उपकरणों का वितरण किया गया है।

इसके अलावा उन्होंने राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई कृषि विश्वविद्यालय के उप-कृषिपति के लिए प्रकाश डाला और उपस्थित किसानों को उपयोग के लिए विद्युत किया। इस सम्बन्ध में उन्होंने किसान समुदाय द्वारा समुचित तकनीक अपनाने के महत्व पर क्रियाकारी भूमिका की गई।

इस दौरान सिक्किम विश्वविद्यालय के उप-कृषिपति लोगों को कृषि और पशुपालन के पेशे को अपनाने हेतु प्रोत्साहित किया। साथ ही उन्होंने उत्पादकता तकनीकी उपकरणों के उपयोग के लिए विद्युत किया। इस सम्बन्ध में उन्होंने किसानों को विद्युत किया। इस प्रशिक्षण से जीवन रक्षक पेशे के लिए प्रकाश डाला। वहीं उन्होंने सभी कार्यों के उपयोग के लिए विद्युत किया। विद्युत किया। इस सम्बन्ध में उन्होंने किसानों को विद्युत किया। विद्युत किया।

जीटीए प्रशासन की पहली बैठक में शामिल हुए सभा सद

पाल्टन तमांग

अनुगामिनी का.सं.

कालिम्पोंग, 20 सितम्बर। गोरखालैंड क्षेत्रीय प्रशासन की पहली बैठक दर्जिनों में संपन्न हुई। बैठक में शामिल होने के बाद कालिम्पोंग 36 नंबर समाज के सभासद पाल्टन तमांग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए बैठक के विषय की जांच की।

सत्तारुद्ध भारतीय गोरखा डेमोक्रेटिक फ्रंट की ओर से कई प्रस्तावों को सामने रखने की बात बताते हुए उन्होंने चर्चा के बाद आम लोगों के लिए प्रसादाव का समर्थन भी किया। विद्युत कृषि के लिए विद्युत किसानों को बेहतरी हेतु कृषि करने का आह्वान करते हुए इस रिसा में अपना हर सम्भव सहयोग प्रदान करने का आशय बताया गया। विद्युत कृषि के लिए विद्युत किसानों को बेहतरी हेतु कृषि करने का आह्वान करते हुए इस रिसा में अपना हर सम्भव सहयोग प्रदान करने का आशय बताया गया।

उन्होंने यह भी कहा कि उन्होंने

प्रतिभागियों से दो दिवसीय इस प्रशिक्षण सत्र से जीवन रक्षक पेशे करने का आशय बताया गया। उन्होंने राज्य के लिए कृषि क्षेत्र में उल्लेखनीय परिवर्तन लाने का कहा कि खेती की मुश्किलों को आग्रह किया। वहीं उन्होंने राज्य में केरल प्रशिक्षण के तहत राज्य के लिए कृषि क्षेत्र में उल्लेखनीय परिवर्तन लाने का कहा कि खेती की मुश्किलों को आग्रह किया। वहीं उन्होंने राज्य में केरल प्रशिक्षण के तहत राज्य के लिए कृषि क्षेत्र में उल्लेखनीय परिवर्तन लाने का कहा कि खेती की मुश्किलों को आग्रह किया।

आवेदकों को इसपर होने वाली सकते हैं। उसी दिन शाम को उन्हें उनके आवेदन की स्वीकृत





## रूस से तेल खरीद सही

आखिर यूक्रेन पर भारत की नीति उपयुक्त परिणामों की कसौटी पर सही साबित होने लगी है। युद्ध शुरू होते ही भारत पर इस बात का दबाव पड़ा शुरू हो गया था कि वह रूस के खिलाफ खुलकर स्टैंड ले। हालांकि पारंपरिक तौर पर गुटनिपेक्ष अंदोलन के नेता के रूप में भारत ने शीत युद्ध के दौरान भी दोनों महाशक्तियों से समुचित दूरी बनाए रखी थी। लेकिन पिछले तीन दशकों में दुनिया के बे सारे समीकरण बदल चुके थे। जहां भारत और अमेरिका काफी करीब आ चुके हैं, वहीं रूस भी सोवियत संघ वाली हैसियत से काफी दूर आ चुका है। जाहिर है, बदले हालात में दुविधा भी बढ़ी थी। अमेरिका और पश्चिमी देशों की अपनी अपेक्षाएं थीं, उन अपेक्षाओं का दबाव भी था, लेकिन भारत के सामने चुनौती थी अपने राष्ट्रीय हितों पर आधारित स्वतंत्र विदेश नीति को जारी रखने की।

भारत ने पूरी दृढ़ता और समझदारी के साथ अपनी नीति पर चलना जारी रखा। युद्ध का विरोध और अंतरराष्ट्रीय शांति की हिमायत करते हुए भी भारत ने अपने पुराने मित्र रूस की निंदा करने की पश्चिमी देशों की जिद स्वीकार नहीं की। यही नहीं, रूस पर लगाए जाने वाले प्रतिबंधों की अनदेखी करते हुए उसने न केवल पहले हो चुके हथियार सौदों पर बेहिचक अमल किया बल्कि उससे सस्ता तेल आयात करने के अपने अधिकार पर भी कोई आंच नहीं आने दी। यह एक ऐसा मसला था जिस पर अमेरिका और पश्चिमी देशों ने पहले इशारों में और फिर खुलकर नाखुशी जारी, लेकिन भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने साफ-साफ कह दिया कि रूस से सस्ता तेल लेना भारत के हित में है और वह अपने राष्ट्रीय हितों से कोई समझौता नहीं करेगा।

नतीजा यह कि इस अवधि में रूस से तेल का आयात लगातार बढ़ता रहा और भारत रूसी तेल का चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा खरीदार बन गया। युद्ध से पहले तक देश की कुल तेल खरीदारी में रूसी तेल का हिस्सा मात्र एक फीसदी हुआ करता था, वह अब बढ़कर 12 फीसदी तक पहुंच चुका है। इस सस्ते तेल की खरीदारी से भारत को अब तक 35000 करोड़ रुपये की बचत हुई है। हालांकि यह सही है कि तेल सरकार नहीं खरीदती, सार्वजनिक और निजी क्षेत्र की रिफाइनरी कंपनियां खरीदती हैं। लेकिन फिर भी सस्ता तेल आना अर्थव्यवस्था के लिए कई तरह से फायदे मंद होता है। यह जहां कीमतों को कम रखता है वहीं देश का आयात बिल और डॉलर की मांग पर अंकुश रखते हुए करांट अकाउंट डेफिसिट को भी नियंत्रित रखने में मदद करता है।

## ज्ञानवापी मस्जिद मामला : बेहद अहम है निर्णय

### अब्देश कुमार

वाराणसी जिला न्यायालय द्वारा ज्ञानवापी मस्जिद मामले को सुनवाई के बोयामाने को गलत बताने वाले न्यायालय को कठोरे में खड़ा कर रहे हैं। यह दुर्भाग्यपूर्ण है। वास्तव में यह महत्वपूर्ण फैसला है।

सामाज्य तौर पर देखें तो कहा जा सकता है कि इन्हें सधन विवाद का मामला न्यायालय में है तो उसको सुनवाई के बोयाकर देना बिलकुल स्वाभाविक है। किंतु मुस्लिम पक्ष की ओर से मुकदमा लड़ रहे अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेंटे ने इसी बात पर पहली कानूनी लड़ाई लड़ी की कि यह मामला सुनवाई के बोयाहै ही नहीं। जिस तरह के तर्क न्यायालय में हैं दिए गए, उनसे एकवारी लगाने लगा था कि कहीं मामला उत्तराधि न हो। यह मुस्लिम पक्ष के बोयालय के बिना लड़ाई लड़ी की कि यह मामला सुनवाई की ओर वह कानून से अनजान है। ऐसे में धरा 85 इस मामले में लागू नहीं हो सकती। याचिका में सिर्फ पूजा की इजाजत मांगी गई है संपर्क का स्वामित्व नहीं। काशी विनाथ मंदिर कानून, 1983 के संदर्भ में भी न्यायालय की टिक्कापाणी महत्वपूर्ण है। इन्हें पर्याप्त कहा है कि पूजा के अधिकार के दावे सुनें के लिए कानून में निषेध नहीं है। मुस्लिम पक्ष सवित्र करने में विफल रहा कि यह मामला विनाथ मंदिर कानून के तहत आता है। जिला न्यायालय के समक्ष यह मामला मां श्रृंगार गौरी की पूजा के अधिकार से संबंधित है। पिछले वर्ष पांच महिलाओं को राखी दी गई थी। सर्वोच्च न्यायालय में विरोध अनुमति याचिका दाव की गई थी। सर्वोच्च न्यायालय ने उनकी दलीलों को खारिज करके वीडियोग्राफी पर रोक लगाने से इनकर किया। बस केवल मामला सामाजिक स्विल न्यायालय से जिला न्यायालय को भेज दिया। सर्वोच्च न्यायालय के देख लिया जाए तभी अंदर क्या है? जिनें दृश्य समाने आए हैं उनसे बहुत साफ दिखता है कि अंदर के निर्णय को मस्जिद मानना कठिन है। हिंदुओं के शिवलिंग के दावे के विपरीत उसे फव्वारा बताने पर बहस अभी खत्म नहीं हुई है। 20 अक्टूबर के सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष यह मामला सुनवाई के लिए आधिकार पर आय था नहीं। इलाहाबाद उच्च न्यायालय में ज्ञानवापी मस्जिद के स्वामित्व को लेकर चल रहा है, जिसकी सुनवाई 28 सितम्बर को होगी। उसके फैसले से तय होगा।

फैसला 26 फतों का है। न्यायालय ने पूजास्थल कानून के संदर्भ में भी अपना मत स्पष्ट किया है। इसने लिखा है कि हिंदू पक्ष का कहना है कि वे 15 अगस्त, 1947 के पहले से साल 1993 तक ज्ञानवापी में प्रतिविन श्रृंगार गौरी की पूजा कर रहे थे। ऐसे में इसका कानून की धारा 35 सी तक तहत वर्जित नहीं है। लिहाजा इसे निरस किया जाता है। न्यायालय की टिक्कापाणी और फैसले से साफ है कि मुस्लिम पक्ष ने मामले को लटकाने के लिए सारे तर्क दिए थे। सच यही है कि अभी तक ज्ञानवापी से संबंधित मामलों में मुस्लिम पक्ष की ओर से ऐसे कोई प्रमाण नहीं पड़ता व्यक्तिके उपरके सामने पांच महिलाओं का केस है।

जिला न्यायालय के बारे में न्यायालय ने अपनी टिक्कापाणी में कहा है कि याची गैर मुस्लिम है और वह कानून से अनजान है। ऐसे में धरा 85 इस मामले में लागू नहीं हो सकती। याचिका में सिर्फ पूजा की इजाजत मांगी गई है संपर्क का स्वामित्व नहीं। काशी विनाथ मंदिर का दावा 1983 के संदर्भ में भी न्यायालय की टिक्कापाणी महत्वपूर्ण है। इन्हें पर्याप्त कहा है कि पूजा के अधिकार के दावे सुनें के लिए कानून में निषेध नहीं है। मुस्लिम पक्ष सवित्र करने में विफल रहा कि यह मामला विनाथ मंदिर कानून के तहत आता है। जिला न्यायालय के समक्ष यह मामला मां श्रृंगार गौरी की पूजा के अधिकार से संबंधित है। पिछले वर्ष पांच महिलाओं को राखी दी गई थीं। शिक्षा प्राप्त करने के लिए लड़कियों को कायुल छोड़ने की अनुमति नहीं है। अगर माहिलाओं की नीकी का मुद्दा इत्यादि। इसका कारण यह है कि देश में अब तक समावेशी सरकार कायम नहीं हो पाई है। हय तय हुआ था कि सरकार में सभी समुदायों और वर्गों का प्रतिनिधित्व होगा। पर अभी तक ऐसा नहीं हो सका। कर्मसुकार में पर्याप्त और उच्चका की है।

इसकी मुख्य लड़ाई सनातन संस्था लड़ रही थी, जिसने पांचों महिलाओं द्वारा याचिका डलवाया

मामला पूजा स्थल (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 1995 और उत्तर प्रदेश की धारा 35 सी तक ज्ञान तथा इनके साथ खड़े कुछ लोगों से मतभेद के राजन संस्था ने इन दोनों को मुकाबले से अलग कर दिया था। बाद में कुछ लोगों ने इनमें से चार महिलाओं को तोड़का अपने साथ लिया तथा उनके वकालतनामा पर दोनों पिलायु-पुकर मुकदमा लड़ रहे हैं, लेकिन इससे न्यायालय को कोई फर्क नहीं पड़ता व्यक्तिके उपरके सामने पांच महिलाओं का केस है।

किंतु जैन, विष्णु जैन तथा इनके साथ खड़े कुछ लोगों से अलग कर दिया था। बाद में कुछ लोगों ने इनमें से चार महिलाओं को तोड़का अपने साथ लिया तथा उनके वकालतनामा पर दोनों पिलायु-पुकर मुकदमा लड़ रहे हैं, लेकिन इससे न्यायालय को कोई फर्क नहीं पड़ता व्यक्तिके उपरके सामने पांच महिलाओं का केस है।

साथ जो सामग्री मिली है खालिकर शिवालिंग उसके कार्बन डेटिंग की मांग भी की जाएगी ताकि उसकी आयु सीमा का निर्धारण किया जा सके।

कहने का तात्पर्य कि मामला मां श्रृंगार गौरी की पूजा का जस्तर है, यांत्रिक विकार और अंदर के अधिकार पर बहस में यह भी तय होगा कि वह वार्कई मस्जिद पर आंदर के वीडियोग्राफी सर्वे का अदेश दिया था तब भी मुस्लिम पक्ष ने इसे रोकने के लिए पूरा जोर लगाया था। सर्वोच्च न्यायालय में विरोध अनुमति याचिका दाव की गई थी। सर्वोच्च न्यायालय के देख लिया जाए तभी अंदर क्या है? जिनें दृश्य समाने आए हैं उनसे बहुत साफ दिखता है कि अंदर के निर्णय को मस्जिद मानना कठिन है। हिंदुओं ने जिला न्यायालय में आगली सुनवाई 22 सितम्बर को है और हिंदू पक्ष की शिवलिंग के दावे के विपरीत उसे फव्वारा बताने पर बहस अभी खत्म नहीं हुई है। 20 अक्टूबर के सर्वोच्च न्यायालय में ज्ञानवापी मस्जिद के स्वामित्व को लेकर चल रहा है, जिसकी सुनवाई 28 सितम्बर को होगी। उसके फैसले से तय होगा।

**महिला विधायकों को सीएम योगी ने लिखा पत्र, कहा- ‘मिशन शक्ति’ से बदली प्रदेश की छवि**



लखनऊ, 20 सितम्बर (एजेंसी)। यूपी के विधानसभा और विधायक परिषद में एक दिन की कार्यवाही महिला विधायकों को समर्पित करने के एतिहासिक पौरों से तीक पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महिला विधायकों को पत्र लिखा है।

दोनों सदनों की सभी महिला सदस्यों को लिखे इस पत्र में मुख्यमंत्री ने महिलाओं की सुक्षमा, समान एवं स्वाकल्पनिक दोहराई है, साथ ही आगामी मिशन अंतर्गत अब तक के प्रयासों और परिणामों का पूरा विवरण भी उपलब्ध कराया है। भारत में सीएम योगी ने लिखा है कि मिशन शक्ति के अन्तर्गत केन्द्र एवं राज्य सरकार की महिला सशक्तिकरण से जुड़ी योजनाओं और कार्यक्रमों के प्रभावी क्रियान्वयन से देश



## क्वाट्रसेप पर कारोबार को बढ़ावा देने के लिए मेटर ने सेल्सफोर्स के साथ किया करार

सैन फ्रांसिस्को, 20 सितम्बर (एजेन्सी)। मेयर के संस्थापक और सीईओ मार्क जुकरबर्ग ने मंगलवार को सॉफ्टवेर कंपनी सेल्सफोर्स के साथ साझेदारी की घोषणा की, जहां कंपनियां अपने ऐस्टोर्कर्म पर व्हाट्सएप बिजनेस मैसेज का इस्तेमाल ग्राहकों के सवालों के जवाब देने, मार्किंग अभियान चलाने और सीधे चैट में बेचने के लिए कर सकती हैं।

जुकरबर्ग ने एक फेसबुक पोस्ट में कहा, 'अधिक से अधिक लोग टेक्स्ट पर व्यवसायों के साथ संवाद करना पसंद करते हैं। इसलिए हमने इस साल की शुरूआत में अपना क्लाउड एपीआई लॉन्च किया था और अब सेल्सफोर्स के साथ साझेदारी कर रहे हैं।'

नया एकीकरण व्यवसायों को व्हाट्सएप पर ग्राहकों के साथ चैट करने के अनुभव बनाने में मदद करेगा, जबकि सीधे सेल्सफोर्स ख्लेटफोर्म से संचार का प्रबंधन करने में सक्षम होगा।

मेयर में बिजनेस मैसेजिंग के बीची मैथ्रू ईडेमा ने कहा, 'हम चाहते हैं कि अधिक से अधिक लोग तेजी से, समझ इंटरैक्शन से लाभान्वित हों और हम व्यवसायों को व्हाट्सएप पर उठने और चलाने



के लिए इसे त्वरित और आसान बनाने के तरीकों में विवेश करना जारी रखे हैं।' कंपनी ने कहा कि दुनिया के सबसे बड़े ग्राहक संबंध प्रबंधन (सीआरएम) प्लेटफोर्म सेल्सफोर्स के साथ साझेदारी करके, कई और व्यवसाय अपने ग्राहकों से जुड़ने के लिए व्हाट्सएप का उपयोग करने में सक्षम होंगे।

कंपनी ने कहा, 'उदाहरण के लिए, एकीकरण के लिए पायलट एक डिवाइस के रूप में, लोरियाल ग्रुप ब्रांड्स व्हाट्सएप का उपयोग क्लाउड एपीआई (एप्लिकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफ़ेस) के साथ वैश्विक स्तर पर सभी आकारों के व्यवसायों के लिए मोबाइल मैसेजिंग प्लेटफोर्म खोलने की घोषणा की।

इस कदम के साथ, कोई भी व्यवसाय या डेलीपर आसानी से सेवा तक पहुंच सकता है, अपने अनुभव को अनुकूलित करने के लिए एक हिस्से के रूप में, लोरियाल ग्रुप ब्रांड्स व्हाट्सएप के शीर्षी पर निर्माण कर सकता है और सुरक्षित व्हाट्सएप क्लाउड एपीआई का उपयोग उन उपभोक्ताओं के साथ फिर से जुड़ने के लिए एक शारीरिक कार्ट में आइटम छोड़ चुके थे और उहाँ कूपन और चैट थ्रोड पर सही ऑफर भेजेंगे।

मेंटा-व्हाट्सएप व्यापार एकीकरण को और बढ़ावा देने के

## मदर डेयरी को 2022-23 में कारोबार 20 प्रतिशत बढ़कर 15,000 करोड़ रुपए होने की उम्मीद

नई दिल्ली, 20 सितम्बर (एजेन्सी)। मदर डेयरी को उम्मीद है कि उत्पादों की बेहतर मांग के कारण चालू वित्र वर्ष में उसका कारोबार 20 प्रतिशत बढ़कर लगभग 15,000 करोड़ रुपए तक पहुंच सकता है। दिल्ली-एनसीआर की शीर्ष डेयरी कंपनी के प्रबंध निदेशक ममीष बंदलिश ने यह बताता है। मदर डेयरी, जो खाद्य तेल और फल तथा सब्जियां भी बेचती है, का कारोबार पिछले वित्र वर्ष में 12,500 करोड़ रुपए था।

मदर डेयरी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स प्राइवेट लिमिटेड के प्रबंधन निदेशक ममीष बंदलिश ने पिछले साल ग्रेटर नोएडा में आयोजित आईडीएफ-विश्व डेयरी सम्मेलन के मौके पर बताया, "हमें उम्मीद है कि चालू वित्र वर्ष में कारोबार 20 प्रतिशत बढ़ि के साथ करीब 15,000 करोड़ रुपए तक पहुंच जाएगा।" उहाँने कहा कि यह वृद्धि विभिन्न डेयरी उत्पादों की मात्रा और मूल्यों, दोनों से प्रेरित होगी। बंदलिश ने कहा, "हम



अपने सभी दूध और अन्य डेयरी उत्पादों की मजबूत मांग देख रहे हैं। गर्मियों के दौरान आइसक्रीम की बिक्री में बढ़ोतारी हुई है।"

लॉकडाउन के कारण 2020 और 2021 में आइसक्रीम की बिक्री प्रभावित हुई थी। मदर डेयरी ने पिछले महीने दिल्ली-एनसीआर में दूध की कीमतों में दो रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतारी की थी। कंपनी ने इस साल मार्च में भी दूध की कीमतों में इन्हीं ही बढ़ोतारी की थी।

बंदलिश ने कहा, "पिछले महीने खुदरा कीमतों में बढ़ोतारी के बाद हमारी दूध खरीद लगत कर हरे हैं। कंपनी 'धारा' ब्रांड के तहत खाद्य तेल और 'सफ्ट' ब्रांड के तहत तजे फल और सब्जियों की बिक्री करती है।" यह पूछने पर कि क्या

उत्पादों को बाजार में पेश करने से पहले उसका परीक्षण, नवोन्मेष करने में सक्षम हैं।

उहाँने कहा, वास्तव में इससे उत्पादों को एक नियंत्रित परिवेश में परीक्षण का मौका मिला और उसके बाद आप उसे आगे बढ़ाने में सक्षम हैं ताकि बाजार को उसका लाभ मिल सके तथा अपने-अपने उत्पाद को लेकर नवोन्मेष में तेजी लाए।

उत्पादों को बाजार में पेश करने के लिये एक तरीका निरंतर जुड़ाव को बरकरार रखना है।" डिजिटल मुद्रा को लेकर भारतीय रिजर्व बैंक और वित्र मन्त्रालय की भूमिका से जुड़े एक सवाल के जवाब में उहाँने कहा कि केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा लेकर भारतीय प्रौद्योगिकी से जुड़ी कंपनियों के लिये एक सतत वित्रीय परिवेश में भूमिका निभाने और हरित वित्र के क्षेत्र में विशिष्ट अवसरों का लाभ उठाने को लेकर अवसर है।

सीतारमण ने यह भी कहा कि वित्र मन्त्री के अपने बैज्ञानिक जुड़ाव को बरकरार रखिये।" उहाँने कहा कि सरकार में चाहे प्रधानमंत्री हों, मंत्री हों या नीति अयोग, हर कोई बाजीती, विचारों के आदान-प्रदान के लिए उपलब्ध है। सीतारमण ने कहा, जितना अधिक जुड़ाव होता है, उतना ही अधिक विवास बनता है। इसीलिए मुझे लगता है कि भरोसा प्रौद्योगिकी से जुड़ी कंपनियों अपने

## एसबीआई ने निर्यातकों से बांग्लादेश के साथ रुपए-टका में व्यापार करने को कहा

मुंबई, 20 सितम्बर (एजेन्सी)। एसबीआई ने निर्यातकों से कहा है कि वे बांग्लादेश के साथ डॉलर व अन्य बड़ी मुद्राओं में कारोबार करने से बढ़ें। इसकी जगह पर रुपये और टका की कमज़ोरी का सम्पादन कर रहा है।

बांग्लादेश की 416 अब डॉलर की अर्थव्यवस्था ऊर्जा और भोजन की बढ़ती कीमतों से जूँझ रही है, व्यायोंके रूप-यूकेरन संघर्ष ने अपने चालू खाते के बाटे को बढ़ा दिया है। बाणिज्य मन्त्रालय ने सोमवार को कहा, बाणिज्य मंत्री पीयूष गोविल के द्वारा दो दोर पर इस बारे में चर्चा हुई है।

आरबीआई ने रुपये की विवरण थामने के लिए इस साल जनवरी से ने 24 अगस्त को अपनी सभी

शाखाओं को भेजे पत्र में कहा, वाल में उच्च आयत बिल और डॉलर के मुकाबले बांग्लादेशी टका की कमज़ोरी से वह विवेशी मुद्रा की कमी का सम्पादन कर रहा है। भारत और सज़दी अखेत ने रुपये वरियाल में कारोबार करने के साथ रुपये कार्ड एवं यूपीआई में भी कारोबार करने पर चर्चा कर रहे हैं। बाणिज्य मन्त्रालय ने सोमवार को करियाद दोरे पर इस बारे में चर्चा हुई है।

आरबीआई ने रुपये की विवरण थामने के लिए कर रहा है। शुक्रवार को जारी आंकड़ों के मुताबिक, अकेले जुलाई में ही 19

अरब डॉलर को बेचा गया है। इसके बावजूद अगस्त में डॉलर की तुलना में रुपया गिरकर रिकार्ड 80 होलांकि, अपनी यह 79-80 के बीच ही है। आरबीआई ने 2013 में जून-सितंबर के बीच शुद्ध रुप

से 14 अरब डॉलर की बिक्री की थी।

अर्थशास्त्रियों ने कहा, आरबीआई का विवेशी मुद्रा भंडार इतना ज्यादा है। आरबीआई का विवेशी मुद्रा भंडार

हालांकि, अपनी यह 79-80 के कमज़ोरी को रोकने के लिए एक बड़ा डॉलर की बिक्री कर सकता है।

शहरी विकास मंत्री फिरहाद हकीम ने बैठक के बाद कहा, पश्चिम बंगाल मैरीटाइम बोर्ड परियोजना के लिए सबसे बड़े बोतीदाता रहे अंडाजी समूह को आशय पत्र जारी करेगा। परियोजना से प्रत्यक्ष रुप से 25,000 लोगों के लिये रोजगार के सुजित होने का अनुमान लगाया जा रहा है।

शहरी विकास मंत्री फिरहाद हकीम ने बैठक के बाद कहा, पश्चिम बंगाल मैरीटाइम बोर्ड एक विवरण तथा सरकार ने ताजपुर में नया समूद्री बंदरगाह अब अडाणी समूद्री बंदरगाह विकसित करने के लिए अडाणी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन को आशय पत्र जारी करने के प्रस्ताव को मंज़ुरी दे रही है। बताया जा रहा है कि इससे 25,000 करोड़ रुपये के निवेश के रास्ता साफ हो गया है। कैबिनेट की बैठक में सोमवार को इस प्रस्ताव को मंज़ुरी दी गई। इससे एक लाख से अधिक रोजगार के सुजित होने का अनुमान लगाया जा रहा है।

शहरी विकास मंत्री फिरहाद हकीम ने बैठक के बाद कहा, पश्चिम बंगाल मैरीटाइम बोर्ड एक विवरण तथा सरकार का निवेश 10,000 करोड़ रुपये होगा। कुल मिलाकर इसमें 25,000 करोड़ रुपये निवेश किए जाएंगे।

उहाँने कहा, बंदरगाह के विकास में 15,000 करोड़ रुपये का निवेश होगा। इसके अलावा बंदरगाह संबंधित बुनियादी ढांचों के विकास के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय निवेश किया जाएगा।

टिक्कटर ने सूचित किया, छवि विवरण उन लोगों को तस्वीर करने में मदद करते हैं जो जब भी एक टिक्कट के लिए एक लोगों के लिए एक बैठक के बाहर आदत बनाने के लिए प्रेरित करता है।



